Regarding need to relax norms for establishment of branches of nationalized banks in tribal areas of Udaipur, Rajasthan-Laid

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : लोकसभा क्षेत्र उदयपुर मुख्यतः जनजाति बहुल क्षेत्र है, जहाँ बिखरी हुई आबादी और पहाड़ी भू-भाग के कारण अनेक स्थानों पर बैंकिंग सुविधाओं का गंभीर अभाव है । उदयपुर जिले के कल्याणपुर, बावलवाड़ा, कनबई, सलूम्बर जिले के जावद, चावण्ड, परसाद, गींगला, सल्लाड़ा, झल्लारा, खरका तथा प्रतापगढ़ जिले के मूंगाणा (धरियावद) सहित कई बड़े गाँवों में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएँ खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही है । केंद्र सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में सैचुरेशन आधारित विकास हेतु धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान सहित अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं । साथ ही, पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं के मानकों में भी जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष छूट दी गई है, जिससे बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्रोत्साहन मिला है । सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गाँव के 5 किमी के दायरे में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है, किंतु जनजाति बहुल क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियोंपहाड़ी मार्ग, बिखरी बसावट और सीमित परिवहनको देखते हुए यह दूरी 2.5 किमी निर्धारित किया जाना आवश्यक है । अतः विनम्र निवेदन है कि जनजाति क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएँ खोलने के मानकों में व्यावहारिक छूट प्रदान की जाए, ताकि जनजाति क्षेत्र के व्यापारी, किसान और आमजन को सुगम व समान बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें ।